आकाशवाणी शिमला

17.07.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

भेंट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा उपरांत आकंलन के तहत 9 हजार 42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और कहा कि यह मामला मंत्रालय के पास लम्बित है और इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के चलते राज्य को इस धनराशि की तत्तकाल आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने एन.डी.आर.एफ. के अंतर्गत लम्बित करीब 60 करोड़ रुपये की राशि भी शीघ्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत मंत्रालय को प्रस्तुत एक सौ 25 करोड़ 84 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना को भी जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में एन.डी.आर.एफ. परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री

इस बीच नई दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट की और सड़क परियोजनाओं से जुड़ी मांगों को उनके समक्ष रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से रानीताल–कोटला और घुमारवीं–जाहू–सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने राज्य में पिछले वर्ष बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार से एक सौ 72 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि भी जारी करने की मांग की। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी मामलों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ठेकेदारों को सभी परियोजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर राजनैतिक प्रतिशोध के चलते पूर्व सरकार की लोकप्रिय योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली शगुन योजना का पैसा भी रोक दिया है और बजट होने के बावजूद भी बेटियों की शादी पर पैसा नहीं दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक जिले में शगुन योजना के सैंकड़ों की संख्या में आवेदन लम्बित पड़े हैं और लोग धनराशि के लिए इधर–उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जिस तरह से पूर्व सरकार की जनहितैशी योजनाओं को बंद करने या रोकने का काम कर रही है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा कार्यकाल में शगुन योजना की शुरूआत हुई थी जिसके तहत बी.पी.एल. परिवार की बेटियों की शादी में 31 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

बजट सत्र

केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा।

इंटक

हिमाचल प्रदेश इंटक इकाई ने राज्य पथ परिवहन निगम को रोड़वेज का दर्जा देने की मांग की है। इंटक के अध्यक्ष बबलू पंडित ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस निर्णय से निगम का सभी तरह का वितीय लेन देन निगम के बजाए विभागीय स्तर पर सरकार के पास होगा और बजट का प्रावधान भी हो सकेगा। इसके अलावा इंटक ने निगम के पीस मील वर्करों को अनुबंध पर लाने और चालकों व परिचालकों के बकाया ओवर टाइम व नाइट भत्ते का भुगतान करने सहित सभी वेतन विसंगतियों को दूर करने और करूणामूलक आश्रितों की अनुबंध के स्थान पर नियमित भर्ती किए जाने की मांग की है।

महासंघ

हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी व कानूनगो महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक आज कुल्लू में हुई। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार द्वारा पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर करने पर कड़ा विरोध जताया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार इस निर्णय को नहीं बदलती है तो महासंघ किसी भी स्तर पर आंदोलन कर सकता है। इस दौरान पटवारी व कानूनगो से जुड़ी कई अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई।

————————————————